

Appendix

SCHEDULE

(The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006)

S.No. Names of the Institutions of Excellence, etc.

1. Homi Bhabha National Institute, Mumbai and its constituent units, namely:-
  - (i) Bhabha Atomic Research Centre, Trombay;
  - (ii) Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam;
  - (iii) Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore;
  - (iv) Institute for Plasma Research, Gandhinagar;
  - (v) Variable Energy Cyclotron Centre, Kolkata;
  - (vi) Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata;
  - (vii) Institute of Physics, Bhubaneshwar;
  - (viii) Institute of Mathematical Sciences, Chennai;
  - (ix) Harish-Chandra Research Institute, Allahabad;
  - (x) Tata Memorial Centre, Mumbai.
2. Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai.
3. North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong.
4. National Brain Research Centre, Manesar, Gurgaon.
5. Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore.
6. Physical Research Laboratory, Ahmedabad.
7. Space Physics Laboratory, Thiruvananthapuram.
8. Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun.

12-7-17  
17/1/17

(2)

MSR

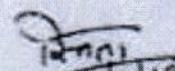
study or faculty so that the number of seats available, excluding those reserved for the persons belonging to the EWSs, is not less than the number of such seats available, in each category, for the academic session immediately preceding the date of the coming into force of this O.M.

- d) Where, on a representation by any Central Educational Institution, the appropriate authority is satisfied that for reasons of financial, physical or academic limitations or in order to maintain the standards of education, the annual permitted strength in any branch of study or faculty of such institution cannot be increased for the academic session following the commencement of this Act, it may permit such institution to increase the annual permitted strength over a maximum period of two years beginning with the academic session following the commencement of this Act; and then, the extent of reservation for the Economically Weaker Sections shall be limited for that academic session in such manner that the number of seats made available to the Economically Weaker Sections for each academic session shall not reduce the number and the percentage of reservations provided for SC/ST/OBC categories.
- e) The scheme for implementing the reservation for the EWS shall be displayed on the website of the institution as soon as possible, but no later than 31st March 2019.

3. The Chairman UGC, Chairman AICTE and Chairperson NCTE and the Bureau Heads of the Department of Higher Education in the Ministry of Human Resource Development responsible for management of the Institutions of National Importance are requested to ensure immediate compliance of this OM.

4. This issues with the approval of the Minister for Human Resource Development.

Encl: As above

  
17/11/19  
(Smita Srivastava)  
Director

- 1. Chairman UGC
- 2. Chairman AICTE
- 3. Chairperson NCTE
- 4. All Bureau Heads of Department of Higher Education

**Copy to:**

**Chief Secretaries of all State Governments/UTs:** with a request to give effect to the provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019 for all higher educational institutions funded/aided, directly or indirectly, by the State Government in such manner that the provision for reservation for EWS would become operational from the academic year 2019-20.



F No: 12-4/2019-U1

Government of India

Ministry of Human Resource Development  
Department of Higher Education

Shastri Bhawan, New Delhi  
Dated: 17 January, 2019

OFFICE MEMORANDUM

**Subject:** Reservation for Economically Weaker Sections (EWSs) for admission in Central Educational Institutions.

In accordance with the provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act 2019, and the reference of Ministry of Social Justice and Empowerment vide OM No. 20013/01/2018-BC-II dated 17th January 2019, enabling provision of reservation for the Economically Weaker Sections (EWSs) who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes, it has been decided to provide reservation in admission to educational institutions subject to a maximum of ten per cent of the total seats in each category. This would not apply to the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India.

2. The provision of reservations to the Economically Weaker Sections shall be in accordance with the directions contained in the OM No. 20013/01/2018-BC-II dated 17th January 2019 of the Ministry of Social Justice & Empowerment and shall be subject to the following:

- a) The reservations shall be provided to EWSs for admission in Central Educational Institutions, (as defined in clause (d) of section (2) of The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006) from the academic year 2019-20 onwards.
- b) The above reservation would not be applicable to the 8 institutions of excellence, research institutions, institutions of national & strategic importance as specified in the Schedule to The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006, as amended from time to time, and appended to this OM, and to the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30 of the Constitution.
- c) Every Central Educational Institution shall, with the prior approval of the appropriate authority (as defined in clause (c) of section 2 of The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006), increase the number of seats over and above its annual permitted strength in each branch of

12-4/2019-U1  
17-01-19

पत्रांक: 02/वि०1-12/2019- ५६३

४९४४  
२६.७.१९ उ

आरबंड सरकार  
उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा निदेशालय)  
गुरुग्राम नगर, होमला ज़िला, हरियाणा, भारत - १२२००२

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद, आठवांसे  
निदेशक।

सेवा मे.

कुलसाहित,  
रीची विश्वविद्यालय, रीची,  
दिनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग,  
सिदो-जान्हु विश्वविद्यालय, दुमका,  
कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा,  
नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू  
डॉ० श्याम प्रसाद मुख्यजी विश्वविद्यालय, रीची,  
दिनोद विहारी नहती कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद,  
झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रीची।

D610  
DL  
27/7/19

रीची, दिनांक : 10/05/2019

विषय :- राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान के संबंध में।

प्रसंग :- मानव संसाधन विकास विभाग का पत्रांक-F. No. 12-4/2019-U1, दिनांक 17.01.2019 एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल ज्ञापांक-1434, दिनांक 15.02.2019

महाराज,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगाधीन पत्रों की छाया प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनुरोध है कि विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासमाजन

अनुलग्नक :- यथोक्त।

४८५१८  
दिनेश प्रसाद  
निदेशक

४८५१८  
२८.७.१९

४८५१८  
२८.८.१९

## झारखण्ड सरकार

### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

#### संकल्प

विषय :— राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने सीधी नियुक्तियों में निहित आरक्षण अनुपात को सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करने का निश्चय किया है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त संख्या में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु सुविधा प्राप्त हो सके और जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार के अंतर्गत व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश प्रशिक्षण से संबंधित नौकरियों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सम्भव हो सके।

2. इस सम्बन्ध में झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा संकल्प सं0-5800, दिनांक—10.10.2002 निर्गत किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विनिर्दिष्ट व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध सीटों के विरुद्ध नामांकन में अनुसूचित जाति हेतु 10 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु 26 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को एक समेकित कोटि मानकर) हेतु 14 प्रतिशत कुल 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

3. भारत का संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग, जो संविधान की धारा 15(4) एवं 15(5) से आच्छादित न हों, के लिए राज्य सरकार को सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) के नामांकन में कुल सीटों का अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान प्रदत्त करने की शक्ति प्रदान की गयी है, जो वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त होगा।

4. “आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग” से अभिप्रेत है; राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक आय एवं आर्थिक प्रतिकूलता के अन्य संकेतकों के आधार पर समय—समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा

वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को छोड़कर अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों का वर्ग।

5. राज्य सरकार ने संविधान के उक्त संशोधन के आलोक में राज्य स्तरीय सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) में नामांकन में आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों के वर्ग हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

6. अतएव पूर्व में निर्गत संकल्प सं0-5800, दिनांक-10.10.2002 को संशोधित करते हुए अब राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) में उपलब्ध सीटों के विरुद्ध नामांकन निम्नलिखित रूप से विनियमित किया जा सकेगा; यथा :—

(क)	खुली गुणाग्रण (मेरिट) कोटि से	—	40 प्रतिशत
(ख)	आरक्षित कोटि से	—	60 प्रतिशत

(2) आरक्षित कोटि की 60 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ निम्न रूपेण होंगी :—

(क)	अनुसूचित जाति	—	10 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति	—	26 प्रतिशत
(ग)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)	—	08 प्रतिशत
(घ)	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2)	—	06 प्रतिशत
(ङ)	आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग))	—	10 प्रतिशत
	एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)	—	
		कुल	60 प्रतिशत

7. नामांकन में आरक्षण का विनियमन :—

(1) राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा अनुमान्य आरक्षण प्रतिशत एवं उनके द्वारा समय-समय पर संशोधन आरक्षण प्रतिशत के अतिरिक्त अन्य कोई आरक्षण देय नहीं होगा।

(2) यदि नामांकन हेतु किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो, तो उस वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को निम्नांकित रूप से विनियमित किया जायेगा :—

(क) यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा और यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा।

(ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही कोटि के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन सीटों को निम्नलिखित अधिमानता क्रम से भरा जायेगा :—

- (i) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से।
- (ii) पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से।

(ग) यदि इसके बाद भी सीटें बची रह जाती हैं तो उन्हें सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

(3) यदि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो उन सीटों को सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

8. आरक्षित कोटि के उम्मीदवार की गणना, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, खुली गुणागुण कोटि की 40 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध की जायेगी, न कि आरक्षित कोटि के रिक्तियों के विरुद्ध।

9. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के० के० खण्डलवाल)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

झापांक-14/आ०नी०-०४-०२/२०१९ का।- 14.3.4 /रांची, दिनांक 15/2/19

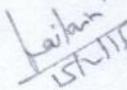
प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-14 / आठनी 0-04-02 / 2019 का।— 1434 / रांची, दिनांक 15/2/19

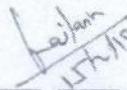
प्रतिलिपि :— महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/निगमों/निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-14 / आठनी 0-04-02 / 2019 का।— 1434 / रांची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :— सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

159

(C)

कापांक-14/अ०नी०-०४-०२/२०१६ का.- 1434, तारी दिनांक 15/२/१२

प्रतिलिपि - महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव  
मुख्यमंत्री सचिवालय, राजी/सचिव भारतगढ विभाग सभा सचिवालय, राजी/प्रधानिकारक  
भारतगढ उपम न्यायालय, राजी/सरकार के तारी विभाग/सभी विभागालय/मुख्य सचिव  
के सचिव/सभी प्रमाणालीय आमुला/सभी उपामुला/विभागालय आमुला, भारतगढ को  
सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रदित।

मन्त्रीम् है कि अपने कठोरतया अधिकारियों/गवर्नर के सभी एवं उपकारी/  
विभागीय/नियायी/परिवटों/विश्वविद्यालयों/गृहविद्यालयों/विद्यालयों को इस नियम से  
बचाव कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

कापांक-14/अ०नी०-०४-०२/२०१६ का.- 1434, तारी दिनांक 15/२/१२

प्रतिलिपि - सचिव, भारतगढ उपम न्यायालय, राजी / सचिव, भारतगढ  
कानौली सचिवालय, राजी को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रदित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

Certified  
5/2/2012  
23/5/2012

(7) 1462

आरक्षण सरकार  
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय - राज्य सरकार विनियोग शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) की पृष्ठमें में राज्य सरकार ने सीधी नियुक्तियों में निहित आरक्षण अनुच्छेद को सरकारी/अद्देसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण प्रतिशत नियोजित करने का नियम लिया है ताकि उभाज के कमज़ोर दण्ड की पर्याप्त सख्ती में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु युक्ति प्राप्त हो जाए और जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार के अनुच्छेद व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश प्रशिक्षण से तब्दित नामांकिती में उनका पर्याप्त प्रतिनियोजित सम्बन्ध हो जाए।

2. इस संकल्प में आरक्षण सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की द्वारा ताक्ता सं-5800 विनाश-10.10.2002 नियंत्रित किया गया है। जिसके द्वारा राज्य सरकार के अधीन व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध सीटों के विरुद्ध नामांकन में अनुसृति जाति हेतु 10 प्रतिशत अनुसृति जनजाति हेतु 26 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को एक समैक्य बोटी भागकर) हेतु 14 प्रतिशत कुल 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

3. भारत का वर्किंग के 103वीं संशोधन अधिनियम 2010 के द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर नामांकितों का वर्ग, जो शिक्षण की धारा 16(4) एवं 15(5) से आफ़ादित न हो, के लिए राज्य सरकार को सरकारी/अद्देसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्परक्षणक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) के नामांकन में कुल सीटों का अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान प्रदान करने की शर्ति प्रदान की गई है, जो वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त होगा।

4. "आर्थिक रूप से कमज़ोर नामांकितों का वर्ग" से अग्रिमत है, राज्य सरकार द्वारा वारियारीक आय एवं आर्थिक प्रतिकूलता के अन्य संकेतकों के आधार पर सम्बन्ध समय वर याता अधिसूचित अनुसृति जनजाति/अनुसृति जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा

(6)

(M61) वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को छोड़कर अन्य वर्गों के आदिक रूप से कमज़ोर नागरिकों का वर्ग।

5. राज्य सरकार ने सहियन के उक्ता संस्थान के आलोक में राज्य सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं लद्दाख शिक्षण संस्थानी (अन्यसंस्थाक शिक्षणीक संस्थानी को छोड़कर) में नामांकन में आदिक रूप से कमज़ोर नागरिकों के वर्ग हेतु 10 प्रतिशत आखण निर्धारित करने का निर्णय दिया है।

6. अतएव पृष्ठे 6 निर्दित राक्षय 80-3800 दिनांक-10.10.2002 को सहायित बनाते हुए अब उक्त राज्य सरकार के अधीन बाहरी राज्य सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं लद्दाख शिक्षण संस्थानी (अन्यसंस्थाक शिक्षणीक संस्थानी को छोड़कर) में उपलब्ध सीटों के विकल्प नामांकन नियमितिका रूप से विनियमित विषय जा सकता यथा :-

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| (i) बुली गुणगुण (सिरिट) कोटि से - | 40 प्रतिशत ✓ |
| (ii) आरक्षित कोटि से -            | 60 प्रतिशत ✓ |

(j) आरक्षित कोटि की 80 प्रतिशत में से आरक्षित उभयदेशी की फिल्म कोटियों की विनियमित विषय बनाती ही -

→ (i) अनुसूचित जाति	-	10 प्रतिशत
→ (ii) अनुसूचित जनजाति	-	25 प्रतिशत
→ (iii) अखण्ड पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)	-	08 प्रतिशत
→ (iv) पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2)	-	06 प्रतिशत
→ (v) आदिक रूप से कमज़ोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त जनजाता (i), (ii), (iii))	-	10 प्रतिशत
एवं (v) में अक्षित वर्गों को छोड़कर)-		60 प्रतिशत
	बुल	

#### 7. नामांकन में आरक्षण का विनियमन -

(i) राज्य से बाहर के अभद्रदेशी के लिए संबंधित शिक्षणीक संस्थान द्वारा अनुग्राम्य आरक्षण प्रतिशता एवं उनके द्वारा समय-समये पर सहियन आखण प्रतिशत के आनंदित्वा उन्होंने आरक्षण देख नहीं होगा।

(2) यदि अभावन होता है किसी आरसित दर्ता के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो उस दर्ता के लिए आरसित सीटों को मिलाइत रूप से विनियमित किया जायेगा।

(3) यदि अनुसृष्टि जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होती तो अनुसृष्टि जाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा और यदि अनुसृष्टि जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होती तो अनुसृष्टि जाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा।

(4) अनुसृष्टि जाति एवं अनुसृष्टि जाति की दोनों कोटि के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन सीटों को मिलाइत अधिभासना कर से भरा जायेगा।

(i) अध्यना पिछड़ा दर्ता के उम्मीदवारी है।

(ii) पिछड़े दर्ता के उम्मीदवारी है।

(iii) यदि इसके बाद भी सीट बची रह जाती है तो उसे सामाज्य कोटि के उम्मीदवारी से भरा जायेगा।

(iv) यदि आरसित कर्ता के कबीलों नागरिकों के दर्ता के पासीना उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होती तो उन सीटों को सामाज्य कोटि के उम्मीदवारी से भरा जायेगा।

v. आरसित कोटि के उम्मीदवार की मण्डा, जो अपने गुणाग्रण के अंतर एवं मूल जाति में खुली गुणाग्रण कोटि की 40 प्रतिशत विविधता की जाएगी, n कि आरसित कोटि की विविधता की विविधत।

9. इस सम्बन्ध में पूर्व में विनियंत रखी राजस्व इस हद तक संशोधित राजस्व जायेगी।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकाय की प्रति भारतीय राजपत्र में जनसामाजिक एवं सूचनाओं प्रकाशित की जाय।

भारतीय राज्यपाल द्वारा आदेश से,

(को १० लो० अष्टलवाल)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

लापाक-14 / आठवीं-०४-०२/२०१९ का- १५.३.१५ / दाता दिनांक १५/२/१९

प्रतिलिपि - नोडल प्रदायिकारी, ई-गवर्न, कार्मिक, व्यासासनिक सुधार एवं राजनीति विभाग, भारत सरकार, दीना को गवर्न के असामाजिक अक में प्रकाशित करने हेतु प्राप्ति।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।



**मयुराक्षी ग्रामीण महाविद्यालय, रानीश्वर**  
 पो.-रानीश्वर, जिला-दुमका (झारखण्ड)  
**MAYURAKSHI GRAMIN COLLEGE**  
 P.O.-RANISHWAR :: DIST.-DUMKA (Jharkhand)  
**S.K.M UNIVERSITY, DUMKA**

NAAC ACCREDITED GRADE 'B'

पत्रांक : .....

दिनांक : .....

2.2 Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/State Govt rules-year wise during the last five year.

Programme Name	SC (10%)	ST (26%)	OBC (14%)	EWS (10%)
BA Hindi (Honours)	30	78	42	30
BA English (Honours)	30	78	42	30
BA Bangla (Honours)	30	78	42	30
BA Urdu (Honours)	30	78	42	30
BA Sanskrit (Honours)	30	78	42	30
BA Santali (Honours)	30	78	42	30
BA Economics (Honours)	30	78	42	30
BA History (Honours)	30	78	42	30
BA Political Science (Honours)	30	78	42	30
BA Sociology (Honours)	30	78	42	30
BA Philosophy (Honours)	30	78	42	30
BA Psychology (Honours)	30	78	42	30
BA Geography (Honours)	20	52	28	20
BA Music (Honours)	30	78	42	30
BA Rural Economics (Honours)	30	78	42	30
BCom (Honours)	30	78	42	30
BSc Chemistry (Honours)	15	39	21	15
BSc Physics (Honours)	15	39	21	15
BSc Mathematics (Honours)	20	52	28	20
BSc Botany (Honours)	15	39	21	15
BSc Zoology (Honours)	15	39	21	15
Arts General in Hindi, Urdu, English, Bangla, Santhali, Sanskrit, Economics, History, Sociology, Political Science, Philosophy, Psychology, Geography, Music, Rural Economics	10	26	14	10
Science General in Mathematics, Physics, Chemistry, Botany, Zoology	5	13	7	5
Commerce General	5	13	7	5

*[Signature]*  
 Principal  
 Mayurakshi Gramin College  
 Ranishwar Dumka



मयुराक्षी ग्रामीण महाविद्यालय, रानीश्वर  
पो-रानीश्वर, जिला-दुमका (झारखण्ड)  
**MAYURAKSHI GRAMIN COLLEGE**  
P.O.-RANISHWAR :: DIST.-DUMKA (Jharkhand)  
**S.K.M UNIVERSITY, DUMKA**

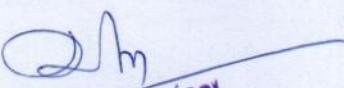
NAAC ACCREDITED GRADE 'B'

पत्रांक : .....

दिनांक : .....

2.2 Number of Seats earmarked for reserved category as per GOI/State Govt rules-year wise during the last five years.

Year	Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule				
	SC	ST	OBC	Gen	Others (EWS)
2020-21	570	1482	798	2280	570
2019-20	570	1482	798	2280	570
2018-19	570	1482	798	2280	570
2017-18	570	1482	798	2280	570
2016-17	570	1482	798	2280	570

  
Principal  
Mayurakshi Gramin College  
Ranishwar Dumka

## सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका

आज दिनांक 27/6/19 को 3:00 बजे अपराह्न में माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) मनोरंजन प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में स्नातकोत्तर विभाग के विभागाध्यक्षों तथा शिक्षकों के साथ बैठक आयोजित किया गया, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए।

उपस्थिति –

1. माननीय कुलपति महोदय	—	अध्यक्ष
2. माननीय प्रतिकुलपति महोदय	—	सदस्य
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण	—	सदस्य
4. विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग	—	सदस्य
5. विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग	—	सदस्य
6. विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग	—	सदस्य
7. विभागाध्यक्ष जन्मुविज्ञान विभाग	—	सदस्य
8. विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग	—	सदस्य
9. विभागाध्यक्ष संताली विभाग	—	सदस्य
10. विभागाध्यक्ष दर्शशास्त्र विभाग	—	सदस्य
11. विभागाध्यक्ष रसायनशास्त्र विभाग	—	सदस्य
12. विभागाध्यक्ष भौतिकी विभाग	—	सदस्य
13. डॉ. विजय कुमार, राजनीतिशास्त्र विभाग	—	सदस्य
14. श्रीमती मेरी मारगेट टुङ्ग कार्यक्रम समन्वयक्	—	सदस्य

सत्र 2019–22 स्नातक सेम-1 (CBCS) में विभिन्न विषयों में नामांकन हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या सुनिश्चित की गयी है जो इस प्रकार है –

कला के विभिन्न विषयों में अधिकतम नामांकन 300 (तीन सौ)

विज्ञान के विषयों में 150 (एक सौ पचास)

गणित विषय में 200 (दो सौ)

भूगोल विषय में 200 (दो सौ)

कामर्स विषय में 300 (तीन सौ)

विभिन्न विषयों में नामांकन Section आधारित होगा और निर्धारित संख्या से अधिक छात्रों का नामांकन होने पर उन छात्रों की परीक्षा नहीं ली जायगी।

जिन विषयों में छात्रों ने अधिक संख्या में आवेदन दिया है उसे विषय बदलकर दूसरे विषय में नामांकन हेतु प्राचार्य छात्रों को प्रेरित करेंगे।

छात्रों का नामांकन अगर महाविद्यालय में सुविधा उपलब्ध है तो द्वितीय पाली में लिया जा सकता है। छात्रों को यह जानकारी प्राचार्य देंगे कि उनका वर्ग द्वितीय पाली में होगा तथा परीक्षा प्रपत्र भी द्वितीय पाली के तहत भरा जायगा।

W.B.Q  
FEDERAL UNIVERSITY  
DUMKA

जिन विषयों में निर्धारित संख्या से कम आवेदन दिया है उनका नामांकन निर्धारित तिथि के अंदर लिया जाय।

#### नामांकन प्रक्रिया –

जिन विषयों में निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन दिया है उनमें झारखंड सरकार के नामांकन नियमावली को अक्षरशः पालन करते हुए नामांकन सूची निर्गत करना है। इस संबंध में कोई भी दुविधा होने पर अधिष्ठाता छात्र कल्याण से दूरभाष पर किसी भी समय सम्पर्क किया जा सकता है। नामांकन नियमावली का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। झारखंड राज्य के बाहर के आवेदकों के नामांकन का नियम –

1. झारखंड राज्य से बाहर के छात्रों का नामांकन तभी होगा जब वे सामान्य कोटि के छात्रों के साथ मेधा सूची में आयें। राज्य के बाहर के छात्रों को किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
2. किसी भी स्थिति में बाह्य छात्रों का प्रतिशत 15% से अधिक नहीं होगा। अगर नामांकित छात्रों की संख्या के 15% से ज्यादा राज्य के बाहर के छात्रों का नामांकन होने पर विश्वविद्यालय उनकी परीक्षा आदि नहीं लेगी तथा उसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन जिम्मेवार होगा।

#### पंजीयन –

नामांकन के साथ-साथ छात्रों का पंजीयन ऑनलाइन सुनिश्चित करना प्राचार्य का दायित्व होगा। नामांकन और पंजीयन की सारी प्रक्रिया विश्वविद्यालय पोर्टल पर ऑनलाइन होगा। नामांकन के साथ जिन छात्रों का पंजीयन नहीं हो पायेगा उनको परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा।

Migration Certificate के अभाव में या Migration Certificate के समय मांगने पर प्राचार्य उस छात्र के नामांकन हेतु समय विस्तार दे सकते हैं। जो विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन की अंतिम तिथि के पहले होगा।

छात्र Hard copy महाविद्यालय में जमा करेंगे जिसे प्राचार्य विश्वविद्यालय को भेजेंगे।

निर्णय लिया गया कि इसकी प्रति सभी प्राचार्यों को आरक्षण नियमावली के साथ अनुपालनार्थ प्रेषित किया जाय। छात्रों का नामांकन (CBSC) नियमावली के अनुसार लिया जायेगा।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण  
6/5/2019

ज्ञापांक - SKMUL-R-6/362/19

कुलपति  
22/6/2019

दिनांक - 22/06/2019

#### प्रतिलिपि –

1. विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या/प्रमारी प्राचार्य को इस निर्देश के साथ कि लिये गये निर्णय का अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित करें।

D. S. W.  
SKM.University  
Dumka

कुलसचिव  
22/06/2019

Mob.: 9304036539  
E-mail: mgeranishwar@gmail.com  
Website: www.mgcollege.org



मयुराक्षी ग्रामीण महाविद्यालय, रानीश्वर  
पो.-रानीश्वर, जिला-दुमका (झारखण्ड)  
**MAYURAKSHI GRAMIN COLLEGE**  
P.O.-RANISHWAR :: DIST.-DUMKA (Jharkhand)  
**S.K.M UNIVERSITY, DUMKA**

NAAC ACCREDITED GRADE 'B'

पत्रांक : .....

दिनांक : .....

TO WHOM IT MAY CONCERN

Mayurakshi Gramin College, Ranishwar has fixed the intake capacity in General Course of Art, Science and Commerce. The intake seats are as follows:

Arts (General) – 100 seats

Science (General) – 50 seats

Commerce (General) – 50 seats

D. S. W.  
S.K.M. University  
Dumka

22/1  
13/05/22  
Principal  
Mayurakshi Gramin College  
Ranishwar Dumka